राष्ट्रीय ग्रिड को सृदृढ़ बनाने तथा अंतः क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली को विस्तृत करने के लिए पावरग्रिड निम्नलिखित को आंरभ करने की योजना बना रही है:-

II. **निर्माणाधीन**

(i) पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र चन्द्रपुर में 100 मे. वा. एच.वी.डी.सी बैक-टू-बैक का दूसरा 500 मे. वा. पोल।

(ii) पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के मध्य गजुवाका में 500 मे.वा. एच.वी.डी.सी बैक-टू-बैक

(iii) उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र के मध्य बोंगईगांव और मालदा के मध्य 400 के. वी. ।

III. **विचाराधीन**

(i) पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के मध्य बिहार शरीफ से रिहन्द के मध्य सासाराम में 500 मे. वा.

IV. पावरग्रिड द्वारा किए गए अध्ययन निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमुख पारेषण लिंकों की आवश्यकता को सुझाते हैं:-

(i) रायपुर (पश्चिमी क्षेत्र) से राउरकेला (पूर्वी क्षेत्र) तक 400 के. वी. एस. सी.।

(ii) तलचेर-2 पारेषण प्रणाली के एक हिस्से के रूप में पूर्वी क्षेत्र में तलचेर से बंगलौर में दक्षिणी क्षेत्र के मध्य 3000 मे. वा. एच.वी.डी.सी बाईपोल लिंक।

(iii) पूर्वी क्षेत्र में ईब घाटी तथा उत्तरी क्षेत्र में जयपुर के मध्य 3000 मे. वा. एच.वी.डी.सी. बाईपोल लिंक तथा ईब घाटी (पूर्वी क्षेत्र) से राय पुर (पश्चिमी क्षेत्र) तक 400 के.वी.ए.सी. प्रणाली। यह पारेषण लिंक सी.ई.पी.ए. से संबंधित पारेषण का हिस्सा है।

अंतः क्षेत्रीय लिंको को चालू किए जाने के साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विद्युत का अंतरण करना संभव हो जाएगा तथा इससे विद्युत उत्पादन को अधिकतम किया जा सकेगा।

पाकिस्तना से बिजली की खरीद

288. **श्री राम जेठमलानी**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान से बिजली खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप से स्वीकृत दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस खरीदी गई बिजली को भारत में लाने के लिए पारगम्यता व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में पाकिस्तान के आर्थिक सहयोग पर कोई समझौता किए जाने की संभावना है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इस उक्त पारगम्यता व्यवस्था पर कुल होने वाले व्यय का अनुमान क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत को बिजली का निर्यात किये जाने के लिए पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने पाकिस्तानी प्रस्ताव के प्रति अपनी रूचि व्यक्त की है और भारतीय प्रतिनिधि मण्डल पाकिस्तान को भेजन में अथवा पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भारत का दौरा, किए जाने में अपनी इच्छा व्यक्त की है ताकि दोनों देशों के बीच प्रस्ताव के तकनीकी एंव वाणिज्यिक पहलूओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जा सके। पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है।

Private Investment in Power Distribution Sector

289. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Business Standard dated 20th September, 1997 under the caption "Ceiling on profits may be raised-New policy to attract private sector in power distribution planned";

(b) if so, what is the reaction of Government to the observations made therein;

(c) the details regarding the present status of the fresh initiatives proposed to be taken to attract greater private investment power distribution; and

(d) the details of action plan finalised for 1997-98 and result achieved there under so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) No, Sir. However, a news items appeared in Business Standard dated 26th September, 1997.

(b) and (c) The Government of India have appointed a single Member Committee under the Chairmanship of Shri S.J. Coelho. Ex-Chairman. Gujarat Electricity Board to examine the feasibility of privatesation of distribution and to suggest guidelines/legal framework for making distribution of electricity financially viable and attractive. Privatisation of distribution is one of the components of the Reform and Restructuring programmes being considered in the State of Orissa, Haryana & Rajasthan.

(d) No action plan has been finalised so far in this regard. Government of India has been supporting the initiatives taken by the State Governments in privatisation of distribution.

Inclusion of power projects of Andhra pradesh under OECF loan Package

290. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Andhra Pradesh Government have asked the Central Electricity Authority to include two projects under the DECF loan package for 1997-98;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what are the details of the role envisaged for CEA in power generation development?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER >(SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) For 1997-98 under OECF loan package, two projects of Andhra Pradesh, namely (i) Simhadri & Vizag Transmission System (Loan amount 10629 million Yen) and (ii) Srisailam Left Bank Power Station (Loan amount 14.499 million Yen) have been negotiated.

(c) The role envisaged for CEA for power generation development is (i) To advice the State Governments, State electricity Boards, Generating companies or any other agency engaged in generation or supply of electircity on such matters as will enable State Government. Board Generating company or Agency to operate and maintain the power system under their ownership or control in an improved manner and where necessary in coordination with any other agency owning or having the control of another power system and (ii) to develop a sound adequate and uniform national power policy, formulate short-term and perspective plans for power development and coordinate the activities of planning agencies in relation to the control and utilisation of national power resources.

Power Shortage in the Country

291. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Economic Times dated 1st November, 1997 captioned "No Respite from power shortages in short term";

(b) whether it is a fact that delays in installing new power generation capacity is largely responsible for this acute shortage;